

प्रेमक,

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक 14 मई, 2010

विषय:-सरकारी कार्यालय हेतु किराये पर लिये गये निजी भवनों का किराया स्वीकृत करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय मामलों में वित्त विभाग की जानकारी में यह आया है कि सरकारी कार्यालयों के लिए किराये पर लिये जाने वाले निजी भवनों हेतु जिलाधिकारी द्वारा किराया औचित्य प्रमाण-पत्र केवल सर्किल रेट के आधार पर ही निर्गत किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा भवन किराया का औचित्य प्रमाण पत्र मुख्यतः भवन की लोकेशन, स्थिति, भवन का विल्ट-अप एरिया, कारपेट एरिया, मुख्य सड़क से भवन की दूरी, पार्किंग एवं अन्य सुविधाओं आदि को देखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। मकान किराया का औचित्य प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के पूर्व यह भी अवश्य देखा जाए कि किराये पर लिये जाने वाले भवन के आस-पास रजिस्टर्ड लीज पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो भवन किराये पर लिये गये हैं उनमें किराये की क्या स्थिति है। चूंकि राज्य सरकार के कार्यालयों हेतु लिये जाने वाले किराये के भवन के लिए राज्य सरकार एक 'सिक्वोर्ड एन्टिटी' है तथा इसमें भवन स्वामी का किराये का एवं अन्य कोई जोखिम निहित नहीं होता है, अतः इस फ़ैक्टर को भी दृष्टिगत रखते हुए किराये पर लिये जाने वाले भवनों का किराया औचित्य प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए।


2- उक्त के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा केवल सर्किल रेट के आधार पर पूर्व में निर्गत किये गये किराया औचित्य प्रमाण पत्र का पुनरावलोकन (Review) कर लिया जाय। यदि पूर्व में निर्गत किया गया औचित्य प्रमाण पत्र वर्तमान किराये की धनराशि से अधिक है तो उसे तदनुसार संशोधित कर संशोधित किराया औचित्य प्रमाण पत्र निर्गत कर सम्बन्धित

विभागाध्यक्ष एवं प्रशासनिक विभाग को सूचित कर दिया जाय। उपरोक्तानुसार पुनरावलोकित प्रकरणों की सूची एक माह के भीतर वित्त विभाग को भी उपलब्ध करा दी जाय।

3-उपरोक्तानुसार सरकारी कार्यालयों के लिए किराये का औचित्य प्रमाण पत्र जिलाधिकारी स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी करेंगे। अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र इस निमित्त मान्य नहीं होगा।

उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

  
(आलोक कुमार जैन)

प्रमुख सचिव

संख्या-526 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय भवन, माजरा, देहरादून।
- 2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 7- एन0आई0सी, एकक सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(राधा रस्तूड़ी)  
सचिव।